THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) HFC expects to be able to award the contract for implementation of the Namrup Rehabilitation Project by August 1998. The completion of the Project would take 30 months from the award of the contract.

(b) After implementation of the rehabilitation package, the Namrup Units are likely to produce 5.30 lakh MT of urea per annum as against the average annual production of 1.90 lakh MT during the last three years.

(c) The decision in respect of the rehabilitiation of the Namrup units of HFC has already been taken.

उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में निवेश के संबंध में राष्ट्रीय-स्तर पर गिरावट आना

4133. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय-स्तर पर उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में निवेश में लगातार गिरावट आ रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है,

(ङ) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है, और

(च) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल): (क) और (ख) 1992-93 से देश में निम्नलिखित नई उर्वरक क्षमताओं में वृद्धि हुई है:-

(लाख टन प्रतिवर्ष)

यूरिया	57.24
डी. ए. पी.	1.27
अन्य मिश्रित उर्वरक	5.75
एस. एस. पी .	1.00

(ग) और (घ) उर्वरक उत्पान के क्षेत्र के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित देने हेतु अपनाई गई नीति के मुख्य घटक इस प्रकार है:-

(i) घरेलू युरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-सह राजसहायता स्कमी तथा भाड़ा सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(ii) उर्वरक उद्योग की फीड स्टाक, ईधन और रेल संचालन में संयोजन के संबंध में सहायता दी जाती है ।

(iii) उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है।

(iv) उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत मालों की आपूर्ति के संबंध में आयात शुल्क में छूट तथा निर्यात सम लाभ के रूप में रिवायते दी जाती है।

(v) नियंत्रणमुक्त फारफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की जाती पर रियायतों की एक स्कीम लाग की गई है ताकि इनके फार्गेट मूल्यों को कम करके इनकी यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके।

(ङ) और (च) यूरिया पर सब्सिडी की वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने एक वैकल्पिक विस्तृत आधार वाली वैज्ञानिक तथा बारदर्शी पद्धति का सुरक्षा देने तथा इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू नीतियों में और अधिक सामंजस्यता के लिए उपायों की अनुशंसा करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति गठित की गई थी। समिति ने अपूर्ती रिपोर्ट 3.4.1998 को प्रस्तुत कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित किया गया योजना परिचय

4134. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कितना योजना परिष्यय निर्धारित किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल):

1997-98 **में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय**

रसायन और पेर्टो-रसायन विभाग

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	कुल योजना परिव्यय (रु./करोड़)
1.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1340.00
2.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	144.00
3.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	16.00
4.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्थुटिकल्स लिमिटेड	0.05
5.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	3.00
6.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9.00
7.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	1.00
8.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	1.00

उर्वरक विभाग

1.	फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	55.00
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन	41.00
3.	प्रोजेक्टस एंड डिलपमेंट इंडिया लिमिटेड	2.00
4	पायराइट्स, फास्फेट्स केमिकल्स लिमिटेड	6.00
5.	पारादीप फास्पेट्स लिमिटेड	49.50
6.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	37.00

Special Subsidy to Fermers of N.E. States

4135. SHRI W. ANCOU SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Governments have given special subsidy to the farmers of the North East States;

(b) if so, how much subsidy has been given to each of the States;

(c) whether there is any arrangement for receiving the fertilisers in time in each State of North East region; and

(d) whether the subsidy to farmers is common all over India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZER: (DR. A.K. PATE): (a) and (b) There is no subsidy on fertilizers being given directly by the Government of India to the farmers including those in the North-Eastern States nor is it (subsidy) given to the States. The subsidy on fertilizers is indirect and is passed on through the manufactures/importers who are obliged to sell the fertilizers to farmers at the Maximum Retail Prices (MRP) fixed statutorily or otherwise by the Government.

(c) and (d) The States in the North-East have arrangements in place for receiving and marketing of fertilizers through the State agencies and/or private dealers. But in view of the difficulties experienced in the past in reaching fertilizers in time to these States due to inadequacy of rail network. Special Freight Reimbursement Scheme was introduced for urea in lieu of the Equated Freight Scheme w.e.f. 1.4.97. Under this Scheme actual costs of transportation are payable to the manufacturers/suppliers of urea. For decontrolled fertilizers, special dispensation has ben made w.e.f. 1.4.97 for meeting additional costs of transportation to these States under the Concession Scheme of Department of Agriculture & Cooperation.

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड को होने वाला घाटा

4136. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या सरायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड को निरंतर घाटा होने के क्या कारणहैं;